गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 175
दि. 27.10.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

सहारनपुर में टायर फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, दो मजदूरों की मौत, जांच जारी

(जीएनएस)। सहारनपुर। जिले के शेखपुरा औद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर शाम एक टायर फैक्ट्री में भीषण विस्फोट और आगजनी ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। घटना के समय फैक्ट्री में काम कर रहे सात मजदूरों में से दो गंभीर रूप से झुलसकर मौके पर ही दम तोड़ बैठे, जबकि पांच अन्य को सुरक्षित बाहर निकाला गया। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के घरों में रहने वाले लोग सहम गए और फैक्ट्री से उठते काले धुएं के गुबार ने पूरे क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा कर दिया।

जानकारी के अनुसार, यह हादसा फैक्ट्री में वेल्डिंग कार्य के दौरान हुआ। शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि बॉयलर में अत्यधिक दबाव या तकनीकी खराबी के कारण विस्फोट हुआ। फैक्ट्री का उद्घाटन मात्र एक सप्ताह पहले 19 अक्टूबर को औद्योगिक विकास मंत्री जसवंत सैनी और आचार्य प्रमोद कृष्णन की उपस्थिति में किया गया था। प्रशासन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग ने फैक्ट्री के अधिकांश हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, और इसे बुझाने में कई घंटे लग गए।

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का मुआयना शुरू कर दिया है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं, जबकि घायलों का नजदीकी निजी अस्पताल में उपचार जारी है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन ने आसपास के इलाके को सुरक्षित कर दिया और आगजनी से होने वाले संभावित जोखिम को कम करने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है।

इस हादसे ने औद्योगिक सुरक्षा मानकों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय विशेषज्ञों का कहना है कि नए स्थापित

उद्योगों में सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने प्रशासन और उद्योग मालिकों से अपील की है कि कर्मचारी सुरक्षा उपकरण, बॉयलर की नियमित जांच और आपातकालीन निकासी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि विस्फोट के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। कई परिवार अपने घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने बताया कि धमाके की तेज आवाज इतनी थी कि कई किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भी इस दौरान बड़ी मुश्किल से खुद को सुरक्षित बाहर निकाला।

हादसे के बाद यह मामला न केवल फैक्ट्री मालिकों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी चेतावनी बनकर सामने आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उद्योगों में सुरक्षा मानकों का पालन न किया गया और कर्मचारियों को सुरक्षित वातावरण नहीं दिया गया तो भविष्य में ऐसे हादसे बढ़ सकते हैं। प्रशासन ने फैक्ट्री मालिकों से सुरक्षा उपायों और नियमों के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और हादसे की गहन जांच शुरू कर दी है।

सहारनपुर विस्फोट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा की अनदेखी भारी मानव और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। प्रशासन और उद्योग मालिकों के लिए यह घटना एक सबक है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी आर्थिक लाभ को मानव जीवन की कीमत पर खतरे में नहीं डाला जा सकता। फैक्ट्री और आसपास के उद्योगों के लिए यह चेतावनी है कि सुरक्षा मानकों और निगरानी को बढ़ाकर ही भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

पेरिस के लूव्र म्यूजियम से 850 करोड़ मूल्य के गहनों की चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार

(जीएनएस)। पेरिस। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध म्यूजियमों में शुमार लूव्र म्यूजियम से 102 मिलियन डॉलर (लगभग 850 करोड़) मूल्य के कीमती गहनों की चोरी ने फ्रांस और अंतरराष्ट्रीय कला जगत को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में फ्रांस की पुलिस ने शनिवार रात दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने कई अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है, लेकिन अभी उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। पहला आरोपी लगभग रात 10 बजे चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, जब वह देश से भागने की कोशिश कर रहा था। दूसरा आरोपी सीन-सेंट-डेनिस इलाके से गिरफ्तार हुआ। दोनों की उम्र लगभग 30 साल बताई गई है। अधिकारियों का मानना है कि ये दोनों चार लोगों वाले गैंग के सदस्य हैं, जिन्होंने चोरी को अंजाम दिया।

जानकारी के अनुसार, चोरी बेहद योजनाबद्ध और तेजी से की गई। लुटेरों ने म्यूजियम की पहली मंजिल की गैलरी में प्रवेश करने के लिए मूविंग ट्रक और लंबी सीढ़ी का इस्तेमाल किया। भागते समय उन्होंने हीरों और पन्नों से सजा एक ताज गिरा दिया, लेकिन आठ कीमती गहने लेकर भाग निकले। इनमें पन्ना और हीरों वाला हार शामिल है, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी पत्नी को दिया था। इस चोरी में शामिल गहनों की कुल संख्या आठ बताई गई है।

संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, चोरी हुए गहनों में क्वीन मैरी-एमेली और क्वीन हॉर्टेंस का ताज, उनका नीलम का हार, कान का झुमका, मैरी-लुइज़ सेट का पन्ना हार और जोड़ी वाले पन्ना झुमके, ब्रौच, सम्राज्ञी यूजिनी का ताज और ब्रौच शामिल हैं।

लूव्र म्यूजियम की स्थापना 10 अगस्त 1793 को हुई थी और यह पहले भी चोरी की घटनाओं का शिकार हो चुका है। अगस्त 1911 में मोनालिसा चोरी हुई थी, जिसे दो साल बाद इटली से बरामद किया गया। मई 1983 में म्यूजियम से दो कीमती शाही कवच चोरी हुए थे, जिन्हें बाद में बरामद किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हाई-प्रोफाइल चोरी की जांच जारी है और बाकी गैंग के सदस्यों की तलाश की जा रही है। म्यूजियम प्रशासन ने भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस चोरी ने न केवल फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया में संग्रहालय सुरक्षा और कीमती वस्तुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

INS सतलुज ने मॉरीशस में सफलतापूर्वक पूरा किया विशाल हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, भारत-मॉरीशस समुद्री साझेदारी को मिला मजबूत आधार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के आईएनएस सतलुज ने मॉरीशस हाइड्रोग्राफिक सेवा के साथ मिलकर लगभग 35,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह सर्वेक्षण भारत और मॉरीशस के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय में संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य समुद्री तटीय विनियमन, संसाधन प्रबंधन, और दीर्घकालिक पर्यावरणीय योजनाओं को सुदृढ़ करना है।

सर्वेक्षण के दौरान मॉरीशस के छह सरकारी कर्मचारियों ने आईएनएस सतलुज पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस व्यावहारिक प्रशिक्षण में आधुनिक हाइड्रोग्राफिक तकनीकों का परिचय दिया गया, जिससे समुद्री मानचित्रण और महासागर प्रबंधन में क्षमता निर्माण हुआ। नौसेना के अधिकारियों के अनुसार यह पहल भारत और मॉरीशस के बीच सतत समुद्री सहयोग को नए आयाम देगी और दोनों देशों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुभव को साझा करेगी। आईएनएस सतलुज ने मॉरीशस राष्ट्रीय तटरक्षक बल के साथ संयुक्त ईईजेड निगरानी और समुद्री डकैती-रोधी गश्त भी की। इस मिशन के सफल समापन ने दोनों देशों के बीच मजबूत समुद्री सुरक्षा सहयोग और मित्रता की पुष्टि की। यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण 18वां ऐसा मिशन है, जिसे औपचारिक रूप से मॉरीशस को सौंपा गया। मॉरीशस के आवास एवं भूमि मंत्री शकील अहमद

यूसुफ अब्दुल रजाक मोहम्मद और भारत के उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव की मौजूदगी में इसका औपचारिक समापन हुआ।

आईएनएस सतलुज 29 सितंबर को पोर्ट लुईस पहुंचा था। यह मिशन इस वर्ष की 14वीं संयुक्त समिति की बैठक के दौरान हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते के तहत संचालित किया गया। इसके जरिए भारत और मॉरीशस ने हिंद महासागर क्षेत्र में सतत समुद्री सहयोग, सुरक्षित नौवहन, और रणनीतिक समुद्री संबंधों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूती दी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह सर्वेक्षण केवल नौसेना की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, तटीय संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय नियोजन में सहयोग का प्रतीक भी है। आईएनएस सतलुज द्वारा पूरा किया गया यह विशाल हाइड्रोग्राफिक मिशन भारत-मॉरीशस के सतत सहयोग और साझा समुद्री हितों के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है।

ओडिशा में साइक्लोन मोन्था की चेतावनी: सात जिलों में सरकारी छुट्टियां रद्द, राहत और तैयारियों में तेजी

(जीएनएस)। भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने साइक्लोन मोन्था के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य के सात जिलों में सरकारी छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सरकारी कर्मचारियों को मुख्यालय लौटने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि साइक्लोन सीधे राज्य पर बड़ा असर नहीं डालेगा, फिर भी तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना के कारण कई क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम आवश्यक था। बालासोर से गंजाम तक फैले क्षेत्रों के साथ-साथ कोरापुट और रायगड़ा जिले विशेष सतर्कता में रखे गए हैं।

मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि तेज हवाओं और अत्यधिक बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ और पहाड़ी जिलों में भूस्खलन का खतरा है। इसके मद्देनजर सरकार ने बचाव और राहत कार्यों की योजना पहले से ही सक्रिय कर दी है। इसमें संवेदनशील क्षेत्रों में राहत शिविरों की स्थापना, संभावित निकासी और साइक्लोन शेल्टर का सक्रिय होना शामिल है।

राज्य डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF) की टीमों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने आम जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि आवश्यक सहायता समय पर प्रदान की जा सके। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संभावित नुकसान को कम करने के लिए सतर्क रहें और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करें। सरकारी कर्मचारियों

को तत्काल लौटने और छुट्टियां रद्द करने के आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य बिना किसी देरी के संपन्न हो। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि सभी जिलों में संसाधनों की उपलब्धता और कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा, नदी किनारे और तटीय इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि बारिश या तेज हवाओं से उत्पन्न खतरे का समय रहते सामना किया जा सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि मॉन्सून और साइक्लोन जैसी मौसमी आपदाओं में प्रशासन की तत्परता और तुरंत कार्रवाई ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होती है। ओडिशा सरकार ने भी इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए न केवल सरकारी तंत्र को सक्रिय किया है बल्कि आम जनता को भी सतर्क रहने और अनावश्यक जोखिम न लेने की सलाह दी है।

साइक्लोन मोन्था की चेतावनी के मद्देनजर राज्य में स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में भी सुरक्षा उपायों को कड़ाई से लागू करने की तैयारी चल रही है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे तेज हवाओं और बारिश के दौरान बाहर निकलने से बचें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और आपातकालीन निर्देशों का पालन करें।

इस प्रकार ओडिशा सरकार ने साइक्लोन मोन्था को गंभीरता से लेते हुए राज्य के सात जिलों में व्यापक सतर्कता और राहत तैयारियों को सुनिश्चित कर लिया है। इस कदम से यह संदेश भी जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रशासन की तत्परता और नागरिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, और किसी भी आपात स्थिति में नुकसान को न्यूनतम करने के लिए पूरी तंत्रिका सक्रिय है।

कांग्रेस ने घोषित किए स्टार प्रचारकों के नाम, 40 वरिष्ठ नेता करेंगे चुनाव प्रचार

(जीएनएस)। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 40 नेताओं के नाम शामिल हैं, जो पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में राज्य के विभिन्न जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने यह कदम उम्मीदवारों को मजबूत समर्थन देने और जनता तक कांग्रेस के संदेश को प्रभावी ढंग से पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया है। सूची में पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह और अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता शामिल हैं। इन नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि वे बिहार के अलग-अलग जिलों में जनसभाओं, रोड शो और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी की नीतियों और विज़न को जनता तक पहुंचाएँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में पार्टी की प्राथमिकता जनता से जुड़ना और उनके मुद्दों को मुख्यधारा में लाना है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि स्टार प्रचारकों का मिशन केवल चुनावी सभाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय जनता के मुद्दों को समझकर उन्हें समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार तक पहुँचाना भी है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि कांग्रेस की यह रणनीति स्टार प्रचारकों के नामों को जोड़कर चुनावी माहौल में प्रभाव डालने और पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने की महत्वपूर्ण कोशिश है। बिहार में विभिन्न क्षेत्रों के मतदाता सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दों पर संवेदनशील हैं, और कांग्रेस का प्रयास है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और प्रतिष्ठा से मतदाताओं में विश्वास कायम किया जा सके।

अमेरिका ने दिया स्पष्ट संदेश: भारत के साथ दोस्ती के बिना पाकिस्तान के साथ रिश्तों की कोई कीमत नहीं

(जीएनएस)। नई दिल्ली। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया है और यह कह दिया है कि भारत के साथ ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दोस्ती को प्रभावित किए बिना पाकिस्तान के साथ कोई भी रणनीतिक साझेदारी नहीं की जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब दक्षिण एशिया में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका दोनों देशों के साथ अपने सहयोग को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है।

रूबियो ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन यह कदम भारत के साथ गहरे और भरोसेमंद रिश्तों पर असर नहीं डालेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका की विदेश नीति परिपक्व, व्यावहारिक और संतुलित है, और किसी भी रणनीतिक निर्णय में भारत के हित सर्वोपरि रहेंगे। उनके अनुसार, अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ सहयोग करता है, लेकिन यह सहयोग भारत या अन्य मित्र देशों के साथ संबंधों की कीमत पर नहीं होगा।

विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच पुराने तनाव से पूरी तरह वाकिफ है और इसी कारण वह दोनों देशों के साथ दोस्ताना और स्थिर संबंध बनाए रखना चाहता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका का उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थिरता और आतंकवाद नियंत्रण के लिए सभी देशों के साथ सहयोग करना है, लेकिन यह सहयोग हमेशा भारत के साथ दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी के संतुलन में ही किया जाएगा।

पाकिस्तान के साथ हालिया घटनाक्रम पर रूबियो ने कहा कि इस साल जून में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुप्त मुलाकात की थी। इसके बाद सितंबर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन यह सब भारत के साथ दोस्ती को प्रभावित किए बिना किया गया।

रूबियो के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका की विदेश नीति में भारत की प्राथमिकता सबसे ऊपर है। किसी भी समय पाकिस्तान के साथ उठाए गए कदम केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीति का हिस्सा होंगे और भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस बयान ने दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में अमेरिका की स्पष्ट रुख को उजागर किया है और यह संदेश दिया है कि भारत के साथ संबंधों को किसी भी राजनीतिक या रणनीतिक कदम के लिए समझौता नहीं किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की यह नीति पाकिस्तान को यह संकेत देती है कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए उसे भारत के साथ दोस्ताना संबंधों का सम्मान करना होगा। रूबियो का बयान न केवल अमेरिका की भारत-प्रेमी नीति को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अमेरिका अपने रणनीतिक फैसलों में स्पष्ट और पारदर्शी रुख अपनाता है, जिससे दक्षिण एशिया में संतुलन और स्थिरता बनी रह सके।

संपादकीय

थोड़ा-सा सांस लें, थोड़ा-सा खांस लें

बहुत दिनों बाद ऐसी छूट मिली थी, सो खूब पटाखे फोड़े, खूब अनार छोड़े, खूब चक्री चलायी, खूब फुलझड़ियां चलायीं। सच बात है जी, कोर्ट कब-कब इतना मेहरबान होता है। जरा-सी छूट को पूरी छूट में तब्दील कर देने के तो हम उस्ताद ठहरे। उंगली पकड़कर पोंचा पकड़ना इसी को तो कहते हैं। सो कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की जो छूट दी, उसे हमने पूर्ण छूट में तब्दील कर दिया। कोर्ट भी नाराज नहीं है और सच पूछो तो सब खुश हैं। दुकानदार खुश कि उन्हें चोरी-छुपे न तो माल रखना पड़ा और न ही बेचना पड़ा। धड़ल्ले से दुकानों के सामने सजाया और धड़ल्ले से बेचा। खरीददार भी खुश कि चोरी चकारी से पटाखे नहीं खरीदने पड़े। सनातन की रक्षा में सन्नद्ध रहने वाले भी खुश। कम से कम उन्हें खुशी का एक मौका तो मिला। वरना तो वे हमेशा आक्रोश मे ही रहते हैं, गुस्से में तिलमिलाए रहते हैं-सारा जोर हमीं पर चलता है क्या? हमारे त्योहारों पर ही नजर रहती है क्या? इतने वर्षों से खुद जलने वालों ने इस बार पटाखे ही नहीं जलाए, उन पर्यावरणवादियों को भी जलाया, जो हमेशा प्रदूषण के विरोध में डटे रहते हैं, उन ज्ञानियों को जलाया जो आतिशबाजी से होने वाले नुकसान का ज्ञान देते रहते हैं। बल्कि कहते हैं कि ध्रुव राठी को तो उन्होंने सबक ही सिखा दिया। दूसरों को जलाने के चक्कर में हमने खूब घर फूंक तमाशा देखा। अपनी आबोहवा बिगाड़ ली। अब कह रहे हैं कि दिल्ली में एक्यूआई का स्तर पांच सौ को पार कर गया। अरे यार यह कोई शेयर बाजार का सूचकांक है क्या, जो इतनी तेजी से बढ़ाए जा रहे हों। भाई साहब शेयर बाजार का सूचकांक बढ़ने के चाहे कितने ही फायदे हों, एक्यूआई बढ़ने के तो नुकसान ही होते हैं। अरे यार, कोई सोने-चांदी का भाव बढ़ रहा है क्या। और उससे भी खुश कौन है? माना कि दिवाली पर सोने-चांदी का भाव बढ़ता है, पर क्या जरूरी है कि दिवाली पर एक्यूआई भी बढ़े। पर क्या करें, बढ़ता ही है। बल्कि अब तो कहते हैं कि एक्यूआई बताने वाली मशीनें ही बंद कर दी गयी। सरकार आंकड़े-वांकड़े अब जरा कम ही बताती है। पर देखो जी, दिल्ली का नाम टॉप पर तो आ ही गया। सबसे प्रदूषित शहर बन गया। नाम होना चाहिए, बदनाम सही। अब चलो जरा-सा खांस लें। बीस सिगरेट के बराबर धुआं जो पी रहे हैं। बिन पिए शराबी होने की एक्टिंग करने वाले ही खुश क्यों हों, बिन पीए सिगरेटबाज होने की तड़ी भी जमा लो। बारिश से नुकसान की भरपाई तो हम बेशक न कर पाएं, पर बारिश ने जो प्रदूषण धोया, हम उसे वापस ले आए हैं। क्या शाबाशी के हकदार नहीं!

निष्प्रभावी होते मतांतरण रोधी कानून, सरकार के साथ समाज को भी करने होंगे प्रयत्न

> मतांतरण केवल आस्था, उपासना एवं पूजा पद्धति आदि का ही रूपांतरण नहीं है। वह राष्ट्रांतरण भी है। जब तक यह बोध समाज के प्रत्येक वर्ग तक नहीं पहुंचेगा, तब तक मतांतरण रोधी कानून पूरी तरह सफल नहीं हो सकेंगे, भले ही उन्हें कितना कठोर क्यों न किया जाता रहे। मतांतरण रोधी कानूनों को कठोर बनाने के साथ इसके लिए भी प्रयत्न होने चाहिए कि किसी का भी छल-कपट से मतांतरण होने ही न पाए। ये प्रयत्न सरकार के प्रत्येक अंग के साथ समाज को भी करने होंगे।

राजस्थान सरकार ने छल-बल या प्रलोभन के माध्यम से किए जाने वाले मत परिवर्तन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जो 'धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक' पारित किया था, वह राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून बन गया है। इस अधिनियम में जबरन या कपटपूर्ण मतांतरण के विरुद्ध अत्यंत कठोर दंडात्मक प्रविधान किए गए हैं।

इस कानून के अनुसार, मतांतरण से जुड़े सभी अपराध गैर-जमानती होंगे, जिनकी सुनवाई सत्र न्यायालय में की जाएगी और आरोपितों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। मतांतरण का प्रश्न केवल आस्था या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज की एकता, सांस्कृतिक संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से छल-बल, प्रलोभन या लालच के माध्यम से मतांतरण कराने के अनेक मामले सामने आए हैं। भारत जैसे सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र में इस प्रकार की गतिविधियां न केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता के लिए चुनौती बनी हुई हैं, बल्कि वे सामाजिक समरसता को भी कमजोर कर रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में राजस्थान सरकार ने यह कानून बनाकर संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का जबरन या कपटपूर्ण मत परिवर्तन न तो व्यक्तिगत अधिकारों के नाम पर स्वीकार्य होगा और न ही समाज के हित में सहनीय। भारत में मतांतरण सदियों से पोषित, संरक्षित, सुनियोजित वैश्विक अभियान का हिस्सा है। इस्लाम और ईसाइयत द्वारा संचालित मतांतरण की प्रक्रिया ने भारत की सनातन संस्कृति और

दर्शन को उसकी उदारता, सहिष्णुता और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के कारण हमेशा से निशाने पर रखा है। आज देश का शायद ही कोई राज्य ऐसा हो, जहां मतांतरण के कपटपूर्ण धंधे को संगठित रूप से न चलाया जा रहा हो। मतांतरण में लिप्त लोग दलित, वंचित और भोले-भाले निर्धन समुदायों को अपना शिकार बनाते हैं। जब प्रलोभन से बात नहीं बनती, तो वे छल, कपट, झूठे चमत्कार और मिथ्या धार्मिक एवं जातिवादी विमर्श का सहारा लेते हैं। कोई सेवा और चिकित्सा के नाम पर यह धंधा करता है, तो कोई जन्नत-दोजख के बहाने। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि देश के कई क्षेत्रों में मतांतरण ने स्थानीय जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। संपन्न माना जाने वाला पंजाब भी पिछले कुछ समय से मतांतरण कराने वाले पादरियों की सक्रियता का शिकार है।

देश के लगभग दस राज्यों ने मतांतरण रोधी कानून बना रखे हैं। इनमें से कुछ राज्यों ने राजस्थान की तरह अपने मतांतरण रोधी कानून को कठोर भी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, लेकिन इसके बाद भी मतांतरण की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। बीते दिनों ही बरेली से खबर आई कि सुमित मैसी नामक पादरी को उसके साथियों समेत मतांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये लोग सामाजिक रूप से कमजोर तबके को निशाना बना रहे थे। इसके पहले खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मतांतरण रोधी कानून की कुछ धाराओं के बारे में कहा कि वे संविधान की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं।

यह भी ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट चार राज्यों के मतांतरण रोधी कानूनों पर उनसे जवाब मांग चुका है। स्पष्ट है कि मतांतरण रोधी कानूनों को कठोर करने की अपनी सीमाएं हैं। यदि हम मतांतरण रोधी कानूनों के प्रभाव का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि कानून तो बना दिए जाते हैं और उन्हें कठोर भी कर दिया जाता है, पर उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। मतांतरण में लिप्त लोग समाज के जिन वर्गों को अपना शिकार बनाते हैं, उनमें उतनी जागरूकता नहीं होती कि वे इन तत्वों के विरुद्ध समय पर समुचित कानूनी कार्रवाई कर सकें या उनकी तिकड़मों को समय रहते भांप सकें। आखिर कठोर कानून होने के बावजूद मतांतरण के अपराध में संलिप्त सजा पाने वाले आरोपितों की संख्या लगभग नगण्य क्यों है? मतांतरण पर लगाम न लग पाने का एक कारण सामाजिक भी है। आज भी हिंदू समाज जातियों के नाम पर बंटा है। यदि सामाजिक समरसता के भाव को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रबल नहीं किया गया तो विभाजनकारी शक्तियां समाज को बांटने के उद्देश्य में सफल होती रहेंगी।

अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए लालायित राजनीतिक दल कोढ़ में खाज का काम कर रहे हैं। वे जातीय भेदभाव की आग में घी डालते हैं और कई बार मतांतरण रोधी कानूनों की आलोचना करते हैं। मतांतरण रोकने के लिए समाज के भीतर से ही एकता और समरसता की भावना एवं सांस्कृतिक चेतना का संचार होना चाहिए। केवल विचारों के स्तर पर ही नहीं, जमीन पर भी सेवा, सहयोग, शिक्षा एवं चिकित्सा के सहस्रों प्रकल्प तथा संकल्प साकार होने चाहिए।

मतांतरण केवल आस्था, उपासना एवं पूजा पद्धति आदि का ही रूपांतरण नहीं है। वह राष्ट्रांतरण भी है। जब तक यह बोध समाज के प्रत्येक वर्ग तक नहीं पहुंचेगा, तब तक मतांतरण रोधी कानून पूरी तरह सफल नहीं हो सकेंगे, भले ही उन्हें कितना कठोर क्यों न किया जाता रहे। मतांतरण रोधी कानूनों को कठोर बनाने के साथ इसके लिए भी प्रयत्न होने चाहिए कि किसी का भी छल-कपट से मतांतरण होने ही न पाए। ये प्रयत्न सरकार के प्रत्येक अंग के साथ समाज को भी करने होंगे।

प्रेरणा

आधा घंटा बारिश और पूरा शहर पानी में ,एक व्यंग्य की बूंदों से भीगी हकीकत

बरसात के मौसम के औपचारिक अंत की घोषणा हो चुकी थी। सरकारी विज्ञप्तियों के मुताबिक अब मौसम में गुलाबी ठंडक का प्रवेश होना था, और नगर निगम ने राहत की सांस लेकर बरसात विभाग की फाइलें बंद कर दी थीं। मगर प्रकृति ने शायद इन कागज़ी घोषणाओं को पढ़ा नहीं था। उसने अचानक सोचा, चलो देखते हैं प्रशासन कितना तैयार है — और बस, बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस के, आधे घंटे की बारिश भेज दी।

वह बारिश भी कोई मामूली नहीं थी, जैसे किसी मंत्री ने जनता के बीच आकर एक झलक दी हो और पूरा शहर उसकी रैली में फंस गया हो। कुछ ही मिनटों में आसमान से पानी ऐसे बरसा जैसे किसी ने बादलों की टंकी उलट दी हो। दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा गया, सड़कों की लाइटें जल उठीं, लोग अपने-अपने मोबाइल से "लाइव कवरेज" करने लगे। कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने अपने छज्जों से बारिश का वीडियो बनाया, यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड किया ताकि सबको पता चले कि उनके मोहल्ले में पानी सबसे ज्यादा बरसा है — बाकी शहर तो शायद सूखा ही रहा होगा।

नगर निगम का आपदा नियंत्रण कक्ष अचानक सक्रिय हो गया, जैसे किसी सोते हुए शेर को डंडे से जगा दिया गया हो। फोन की घंटियाँ बजने लगीं — "साहब, नाला भर गया है!", "साहब, सड़क पर पानी घुस आया!", "साहब, पेड़ गिर गया है!", "साहब, गाड़ी फंस गई है!"। उधर कक्ष के अधिकारी अपने कानों से फोन हटाकर सोचने लगे कि बरसात तो खत्म हो चुकी थी, तो यह पानी आखिर आया कहाँ से? दरअसल बरसात समाप्त होने

के साथ ही पानी निकासी दल भंग कर दिया गया था। जो कुछ नौसिखिए मौके पर भेजे गए, वे रास्ते में ही सोचते रहे कि काश यह आधा घंटा टल जाता, तो आज का दिन कितना शांत बीतता।

सड़कें जो गर्मियों में उफनते डामर की तरह चमक रही थीं, अब पानी के नीचे गायब थीं। नालियाँ जिन्हें नागरिकों ने "रीसायकल सेंटर" बना रखा था, कबाड़ से भर चुकी थीं। प्लास्टिक के थैले, टूटे खिलौने, पुराने जूते और पूजा के फूल सब मिलकर ऐसे बह रहे थे जैसे किसी त्योहार की विदाई हो रही हो। एक विशाल पीपल का पेड़ जो महीनों से गिरने की कगार पर था, आखिरकार इस बरसात का बहाना पाकर बीच सड़क पर धराशायी हो गया। नियमों में बंधी नगर समिति उसे पहले काट नहीं पाई थी — अनुमति, फाइलें और पर्यावरण संतुलन की बातें बीच में थीं। अब वही पेड़ जब सड़क पर फैला पड़ा था, तो यातायात संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया।

परंतु शहर के कुछ साहसी लोग अपनी बाइकों को पेड़ की शाखाओं के नीचे से निकालकर इस प्राकृतिक अवरोध का मुँह चिढ़ा रहे थे। कारों की लंबी कतारें हॉर्न बजाती खड़ी थीं, जैसे कोई मेला लगा हो। लोग कारों से उतरकर फोटो खींच रहे थे — कोई कहता "देखो भाई, इस बार तो गड्ढा बड़ा हो गया है!" तो कोई जवाब देता "हाँ, खर्चे का अंदाज़ा तो बढ़िया लगा लिया गया था, अब मंजूरी बाकी है।" ठेकेदार की आँखों में भी शायद बारिश की बूंदों के साथ मुस्कान तैर रही थी। आखिर दोबारा मरम्मत का मतलब था दोबारा ठेका, और दोबारा ठेका का मतलब था दोबारा अवसर।

बारिश का यह आधा घंटा जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स था — जिसमें हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा था। बादल गर्जना कर रहे थे, बिजली चमक रही थी, अधिकारी बयान जारी कर रहे थे, नेता ट्वीट कर रहे थे कि "ऐसे मौसम में नागरिकों को घर से निकलना नहीं चाहिए।" नागरिकों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई — किसी ने प्रशासन को कोसा, किसी ने मौसम विभाग को, और बाकी ने भगवान को।

फिर जैसे अचानक आया था, वैसे ही अचानक वह पानी थम गया। आसमान खुल गया, सूर्य ने झांककर देखा — और शहर फिर अपने सामान्य स्वरूप में लौट आया, वही कीचड़, वही जाम, वही तिरछे पड़े बिजली के खंभे और वही उम्मीद कि अगली बारिश तक सब ठीक हो जाएगा। आधा घंटा बारिश बीती तो जरूर, पर अपने पीछे वह पूरा आईना छोड़ गई जिसमें प्रशासन, नागरिक और व्यवस्था — सबके चेहरे साफ-साफ दिखाई देने लगे। बारिश ने किसी को दोष नहीं दिया, उसने तो बस अपना काम किया — बादलों से गिरी, धरती पर बही और फिर आकाश में लौट गई। लेकिन जो धरती पर रह गए, वे आज भी यही सोच रहे हैं कि बरसात का मौसम तो खत्म हो चुका था, फिर यह आधा घंटा क्यों आया? शायद इसलिए कि प्रकृति हर साल हमें यह याद दिलाती है कि उसके आगे न कोई योजना चलती है, न कोई नोटिस — बस पानी की एक फुहार ही काफी है यह दिखाने के लिए कि कितना कागज़ी है हमारा आत्मविश्वास।

प्रकृति व आध्यात्मिक चेतना के प्रति जिम्मेदारी समझें

हिमालय आज रुष्ट प्रतीत हो रहा है और अपनी विप्लवी हलचलों के माध्यम से मानवता को चेतावनी दे रहा है। इंसान ने हिमालय के साथ जो खिलवाड़ किया है, वह चिंताजनक और क्षोभ उत्पन्न करने वाला है। विकास के नाम पर इसके शिखरों, तलहटियों और गोद में अनियोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जो हिमालय की प्राकृतिक विशेषताओं से मेल नहीं खातीं। इन कृत्यों में मानव की अदूरदर्शिता, लोभ, अहंकार और महत्वाकांक्षाएं प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं, जो प्रकृति के प्रति न्यूनतम संवेदना की कमी को दर्शाती हैं।

वर्ष 2025 में प्रकृति ने हिमालय के हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर प्रांतों में विनाशकारी तांडव किया, जिसके भयावह परिणाम पंजाब और दिल्ली तक देखने को मिले और इसका असर प्रयागराज से बनारस तक फैला। यह घटना हिमालय की चेतावनी को सही साबित करती है और समय रहते उसकी संकेतों को समझने और आवश्यक सबक सीखने का संदेश देती है। हिमालय अब तक हमें पर्याप्त चेतावनी दे चुका है, और ऐसा लगता है कि अब वह सीधे कार्रवाई पर उतर चुका है।

ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक मौसम परिवर्तन जैसी घटनाओं में भले ही प्रभावित लोगों का सीधा हाथ न हो, लेकिन इनका नाम लेकर हम अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। अपनी बेवकूफियों और अदूरदर्शिता को छुपाना या प्रकृति-विरोधी योजनाओं को विकास का रूप देना अब नहीं चल सकता। समय आत्मचिंतन, समीक्षा और ठोस सुधार का है। हमें प्रकृति और हिमालय के प्रति न्यूनतम संवेदना के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। अन्यथा, भविष्य में प्रकृति के विकराल दंड से कोई भी बच नहीं सकता।

इस प्राकृतिक आपदा में जिनकी जान गई, उनकी आत्माओं के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए और उनके परिजनों के प्रति हार्दिक सांत्वना जाहिर की जाती है। सभी से यह निवेदन किया जाता है कि प्रकृति के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें। भारतीय चिंतन में प्रकृति को मां के समान माना गया है, जो अपनी संतानों की रक्षा और पोषण करती है। हमें इस मां के प्रति कृतज्ञता और सम्मान के साथ काम करना चाहिए, ताकि उसकी कृपा हम पर बनी रहे। अगर हम प्रकृति को भोग्य वस्तु मानकर उसका अत्यधिक शोषण करते हैं, तो इसके नतीजे को भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होगा। वर्ष 2025 में हिमालय क्षेत्र में शिव-शक्ति से जुड़े तीर्थस्थलों के आसपास प्राकृतिक आपदाएं अधिक आई हैं, जो एक स्पष्ट संकेत हैं कि प्रकृति रुष्ट है। प्रकृति की अधिष्ठात्री मां जगदम्बा और भगवान शिव रुष्ट हैं, और महाकाल-महाकाली अपना ताण्डव नृत्य करने के लिए विवश हो गए हैं। वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक विध्वंस करने के लिए बाध्य हैं, जो हमें प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का संदेश देता है।

वर्तमान में तीर्थ स्थलों को मानव ने पिकनिक स्पॉट और व्यापारिक केंद्र बना दिया है, जहां तीर्थयात्रियों को लूटने का कारोबार होता है, जो तीर्थ की गरिमा के अनुरूप नहीं है। बिना जीवन के सच्चे तप, सुधार और पात्रता के, मुफ्त में भगवान की कृपा की उम्मीद करना और तीर्थ स्थलों में गंदगी फैलाना, यह पूरी तरह से समझदारी के खिलाफ है। इस प्रकार का तीर्थाटन और चिन्हपूजा करना नादानी और नासमझी है, जो जीवन के मूल्यों की न्यूनतम समझ का भी अभाव दर्शाता है। भगवान की कृपा के लिए, व्यक्ति को अपने भीतर न्यूनतम पात्रता अर्जित करनी होती है, जो ईमानदारी, जिम्मेदारी और समझदारी पर आधारित होती है। गैरजिम्मेदार आचरण, बेईमानी और अहंकार से इसका कोई संबंध नहीं है।

प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्रता से भरपूर तीर्थ स्थलों के हृदय क्षेत्र में सड़क, रोपवे और रिजोर्ट्स का निर्माण उचित नहीं है। प्रकृति की गोद में स्थित इन स्थलों का आदर्श एकांत और साधना का वातावरण रहा है, जहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा श्रम करना तप के रूप में माना जाता था। जो लोग अशक्त हैं, उनके लिए कंडी और अन्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जो स्थानीय लोगों के रोजगार का भी कारण बनती हैं। इस तरह की अव्यवस्थित विकास योजनाओं से इन स्थानों की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

वर्ष 2025 के प्रकृति तांडव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नदियों और जल स्रोतों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, और इन्हें हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। इनकी राह में बस्तियां बसाना, मकान, होटल और रिजॉर्ट बनाना गलत है। अंग्रेजों ने अपने समय में जिन हिल स्टेशनों में निर्माण किए, वे आज भी प्रकृति के साथ तालमेल बनाए हुए सुरक्षित हैं। इसके विपरीत, हमने पहाड़ी क्षेत्रों की ढलानों पर जंगलों की सफाई कर बहुमंजिला भवनों की कतारें और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, जो हमारी अदूरदर्शिता और दिवालियापन को दर्शाते हैं। अगर किसी मौसमी बारिश में कुछ दिन और बारिश होती है, तो इसका नुकसान भयंकर हो सकता है और भूकंप के खतरे वाले क्षेत्रों में तो यह नुकसान अकल्पनीय हो सकता है।

हिमालयी प्रांतों में विकास के कर्णधार नेताओं, अधिकारियों, इंजीनियरों और बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अब सचेत हो जाएं और आम लोग भी जागरूक हों। थोड़ी-सी समझदारी, ईमानदारी और प्रकृति के प्रति न्यूनतम संवेदनशीलता से हम इस तरह की त्रासदियों के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।

अभियान

रवि योग में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से बरसेगी सूर्य देव की कृपा, खुलेंगे सौभाग्य के द्वार

कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष जब अपनी मधुर छटा में होता है, तब प्रकृति के हर अंश में एक अद्भुत दिव्यता का संचार दिखाई देता है। खेतों में सुनहरी फसलें लहलहाने लगती हैं, गंगा और पोखरों के तटों पर दीपों की कतारें जगमगाने लगती हैं, और हर दिशा से गूंज उठता है—"जय छठी मइया!"। लोक आस्था का यह महान पर्व छठ पूजा न केवल भारतीय संस्कृति की आत्मा है, बल्कि सूर्योपासना का ऐसा अनुपम उत्सव है जिसमें सूर्य को प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजित किया जाता है। इस वर्ष सोमवार, 27 अक्टूबर को संध्या समय डूबते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा, और उसके अगले दिन मंगलवार, 28 अक्टूबर की प्रभात बेला में उगते सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करके यह चार दिवसीय महापर्व पूर्ण होगा।

वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से इस वर्ष की छठ पूजा विशेष रूप से मंगलकारी मानी जा रही है क्योंकि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के इस पावन दिन रवि योग और सुकर्मा योग जैसे अत्यंत शुभ योगों का संगम बन रहा है। सोमवार की दोपहर 01 बजकर 27 मिनट से आरंभ होने वाला रवि योग पूर्ण रात्रि तक रहेगा। इस योग के प्रभाव से संध्याकाल का अर्घ्य अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। कहा गया है कि जब रवि योग में सूर्योपासना की जाती है, तब भगवान भास्कर स्वयं साधक के जीवन से रोग, क्लेश, और अंधकार को मिटाकर उसे दीर्घायु, तेज और वैभव प्रदान करते हैं।

दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में इस दिन सूर्यास्त का समय लगभग 05 बजकर 40 मिनट रहेगा। जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ते हैं, तब उनका रूप सुनहरी आभा से मंडित हो जाता है। यह वह क्षण होता है जब व्रतीजन अपने हाथों में तांबे या पीतल के कलश में जल लेकर, उसमें दूध, पुष्प, अक्षत और दूब मिलाकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। संध्या की उस लाली में जब जल की धारा सूर्य की किरणों से मिलती है, तब वह दृश्य इतना अद्भुत होता है मानो धरती और आकाश का संगम हो गया हो। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का प्रकृति के प्रति समर्पण है। व्रतीजन उस क्षण अपने भीतर के अहंकार को सूर्य के समक्ष नत कर देते हैं, और प्रार्थना करते हैं—"हे दिव्य तेजस्वी सूर्यदेव, हमारे जीवन में भी अपने प्रकाश का संचार करें।"

ज्योतिषियों का मानना है कि इस बार छठ के दिन कौलव करण और तैतिल करण का महासंयोग बन रहा है। कौलव करण में संध्या अर्घ्य दिया जाएगा, जिसे शुभ माना गया है। यह करण व्यक्ति के कर्मों को स्थायित्व देता है और आरंभ किए गए कार्यों में सफलता का वरदान प्रदान करता है। वहीं अगले दिन तैतिल करण रहेगा, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। तैतिल करण जीवन में सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार कौलव और तैतिल करण के इस दिव्य मेल से छठ पूजा का हर क्षण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहेगा।

जब सूर्य डूबता है तो प्रतीकात्मक रूप से यह त्याग, संयम और आभार का संकेत है। व्रतीजन पूरे दिन उपवास और कठिन व्रत निभाकर संध्या में सूर्य को प्रणाम करते हैं। इस क्षण वे अपने जीवन की सारी नकारात्मकता, दुख और कष्ट सूर्य की किरणों में समर्पित कर देते हैं। कहा गया है कि डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य व्यक्ति के जीवन से बुरे कर्मों का अंधकार दूर करता है। रवि योग के प्रभाव में यह क्रिया और भी शक्तिशाली हो जाती है। सूर्य, जो आत्मा के कारक ग्रह माने गए हैं, अपने भक्त को आंतरिक शुद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करते हैं।

कार्तिक शुक्ल षष्ठी का यह समय सौर ऊर्जा के अत्यधिक प्रभाव का भी काल होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जब सूर्य पश्चिम दिशा में ढलता है, तब वातावरण में अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण इस समय सूर्योपासना से शरीर और मन में संतुलन बनता है। जो लोग रवि योग में सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं, उनके शरीर की प्राणशक्ति में वृद्धि होती है, मन के विकार समाप्त होते हैं और आत्मबल में वृद्धि होती है।

पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान सूर्यदेव को छठी मैया की उपासना अत्यंत प्रिय है। छठी मैया, जिन्हें सूर्य की बहन कहा गया है, अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। एक बार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के घर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मुनि कश्यप के कहने पर छठी देवी की पूजा की। देवी प्रसन्न होकर उन्हें पुत्ररत्न का आशीर्वाद दिया। तभी से छठ पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। इस दिन सूर्य की बहन के रूप में छठी मैया की आराधना की जाती है ताकि परिवार में सुख, संतति और समृद्धि बनी रहे।

रवि योग के इस दिव्य अवसर पर जब लाखों व्रती महिलाएं नदी, तालाब और सरोवरों में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देंगी, तब वह दृश्य केवल भक्ति का नहीं, बल्कि ऊर्जा का महोत्सव होगा। जल में खड़े होकर सूर्य की किरणों को अपने नेत्रों में समाहित करना आत्मा के जागरण का प्रतीक है। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य और सूर्य के बीच का आध्यात्मिक सेतु बनता है। अगले दिन 28 अक्टूबर को जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, तब यह पर्व अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। यह अर्घ्य नयी शुरुआत, पुनर्जन्म और जीवन के पुनरुत्थान का प्रतीक है। डूबते सूर्य को अर्घ्य त्याग का संकेत देता है, तो उगते सूर्य को अर्घ्य प्राप्ति का। यह दर्शाता है कि जीवन में हर अंधकार के बाद एक नया प्रकाश अवश्य आता है।

इस प्रकार रवि योग, सुकर्मा योग और कौलव-तैतिल करण के इस अद्भुत संगम में छठ पूजा न केवल धर्म का उत्सव है, बल्कि आत्मा के प्रकाश का पर्व है। इस दिन किया गया सूर्योपासना का प्रत्येक क्षण व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्य और आत्मिक शांति का मार्ग खोल देता है। जो साधक पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं, उनके जीवन में सदैव प्रकाश की ज्योति जलती रहती है, और वही ज्योति छठ महापर्व की सबसे बड़ी कृपा है — "सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही जीवन है, और सूर्य ही मोक्ष का मार्ग है।"

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

‘मिशन बांग्लादेश’: पाकिस्तानी जनरल साहिर मिर्जा ने ढाका में मोहम्मद यूनुस से की द्विपक्षीय मुलाकात, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पाकिस्तान के ज्वॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अपने आधिकारिक दौरे पर पहुंचे और वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। यह दौरा 24 अक्टूबर को शुरू हुआ और इसमें छह सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल शामिल था। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर विस्तृत बातचीत हुई।

ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में हुई शिष्टाचार मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि यूनुस ने मिर्जा को बांग्लादेश का नक्शा भेंट किया, जिसमें भारत के असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों को भी बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। हालांकि, इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है।

मिर्जा ने अपने दौरे का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन-से-जन संबंधों को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने व्यापारिक और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच पहले से कराची-चटगांव शिपिंग रूट चालू है, जबकि ढाका-कराची एयर रूट जल्द शुरू होने वाला है। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने संयुक्त सैन्याभ्यास, हथियार सौदे और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। साथ ही दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने, मध्य पूर्व और यूरोप में तनाव कम करने और फेक न्यूज से निपटने पर भी सहमति बनाई गई।

1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान-बांग्लादेश संबंध लंबे समय तक ठंडे रहे, लेकिन 2024-25 में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की बांग्लादेश यात्राओं में वृद्धि देखी गई है। मिर्जा के इस दौरे से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को पुनः सक्रिय किया जा रहा है। बांग्लादेश अब पाकिस्तान, तुर्की और चीन से रक्षा सामग्री खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक सहयोग को नई दिशा मिलने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा केवल औपचारिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

गुना में जमीनी विवाद खौफनाक हुआ: दबंगों ने थार से कुचला, अधेड़ की अस्पताल में मौत, महिलाओं पर भी हमला

(जीएनएस)। गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में जमीनी विवाद ने एक खौफनाक और बर्बर रूप ले लिया, जिसमें एक अधेड़ की जान चली गई। रामस्वरूप नागर नामक शख्स को रविवार को उसके ही जमीन के विवाद को लेकर दबंगों ने अपनी थार गाड़ी से कुचल दिया। गंभीर चोटों के बाद रामस्वरूप को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना के समय रामस्वरूप की बेटियां और अन्य महिला परिजन मौके पर मौजूद थे। आरोपियों ने न केवल रामस्वरूप को कुचला, बल्कि महिलाओं के साथ भी मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए। यह पूरी घटना गांव में दहशत और आक्रोश का कारण बनी। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से रामस्वरूप की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, और इस मामले को लेकर तनाव पहले से ही गांव में था।

घटना के बाद गांव में मातम पसरा और लोगों में गुस्सा फैला। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि पुलिस कार्रवाई में देरी करती है तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

पुलिस ने इस गंभीर मामले को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, मौके पर कई सबूत और गवाह उपलब्ध हैं, जिनसे आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और ग्रामीणों के बयानों को भी खंगालना शुरू कर दिया है।

गयाजी में भाजपा नेता के बेटे की हत्या मामले में फरार आरोपित गिरफ्तार, दो कट्टा-पिस्टल बरामद

(जीएनएस)। गयाजी। भाजपा नेता और पूर्व मेयर प्रत्याशी उपेंद्र पासवान के पुत्र सुभाष कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और फरार आरोपित रीतिक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में हत्याकांड में प्रयुक्त दो कट्टा और एक पिस्टल सहित तीन कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल अन्य हथियार भी जब्त किया। पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरली हिल बैरागी मोहल्ला निवासी सुभाष हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार को बागेश्वरी गुमटी मोहल्ला में छुपाया गया है। सूचना की पुष्टि के बाद डेल्हा पुलिस ने छापेमारी की। जब पुलिस रीतिक के घर पहुंची, तो उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन सशस्त्र बल के जवानों ने उसे दबोच लिया। रीतिक की निशानदेही पर अमृत पासवान के घर की तलाशी ली गई, जहां पुलिस को एक कमरे में कपड़े में लिपटा हथियार मिला। इस दौरान दो कट्टा, एक पिस्टल और तीन कारतूस बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल 20 अक्टूबर को हुई हत्या में किया गया था। हत्या की घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें ये हथियार देखे गए थे। इससे पहले गुरारू इलाके में पुलिस मुठभेड़ में तीन अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था और एक हथियार भी बरामद हुआ था। इस तरह कुल मिलाकर अब तक चार आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किए जा चुके हैं। एसपी गयाजी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों से सख्त पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपितों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए टीमों को सक्रिय किया गया है और किसी भी हद तक कार्रवाई की जाएगी। इस गिरफ्तारी से हत्याकांड की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है और पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की है।

मऊ में छठ पूजा का सामान लेकर लौट रहे हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी

(जीएनएस)। मऊ। रानीपुर थाना क्षेत्र के लखनुआड़ीह गांव के पास रविवार की शाम 6 बजे छठ पूजा का सामान लेकर घर लौट रहे हिस्ट्रीशीटर राजेश सिंह उर्फ मंटू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक 45 वर्षीय राजेश सिंह पिरुआ गांव के रहने वाले थे। घटना के समय वह कांझा बाजार से बाइक पर घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आए अज्ञात बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। गोली उनकी सिर और छाती में लगी और वे लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गए।

घटना के तुरंत बाद आसपास से गुजर रहे लोगों ने घायल स्थिति में राजेश सिंह को देखा और पहली नजर में इसे किसी दुर्घटना के रूप में समझा। हालांकि, जल्द ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, रानीपुर एसओ सुभाष कुमार ने तुरंत घायलों को जिला अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रानीपुर थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का मुआयना शुरू कर दिया। एसपी इलामारन भी रात दस बजे घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में जांच और निगरानी बढ़ा दी। उन्होंने बताया कि मृतक हिस्ट्रीशीटर था और इस वारदात के पीछे पुराने विवाद या आपराधिक रूपरेखा की संभावना को नहीं नकारा जा सकता। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ ही पुलिस संभावित गवाहों से भी पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि यह वारदात पूर्व नियोजित थी और इसे अज्ञात समूह ने अंजाम दिया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक क्षेत्र में पहले भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, लेकिन इस समय वे अपने निजी काम और त्योहार के सामान की खरीदारी के लिए बाहर गए थे। घटना ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एसपी इलामारन ने जनता से अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक, मृतक के मोबाइल फोन और निजी वस्तुओं की भी जांच की जा रही है ताकि हत्या के पीछे किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत मतभेद की वजह सामने आ सके।

महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, खिलाड़ियों को सुरक्षा के लिए प्रशासन से संपर्क रखने की सलाह

(जीएनएस)। नई दिल्ली। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना ने देशभर में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खिलाड़ियों और खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी चाहे कहीं भी खेल के लिए जाएं, उन्हें स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों को अपनी मौजूदगी की जानकारी देना चाहिए। उनका कहना है कि यह घटना हम सभी के लिए एक सबक है और खेल समुदाय को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

विजयवर्गीय ने बताया कि जैसे आम नागरिक अपनी यात्रा या किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान कम से कम एक स्थानीय व्यक्ति को अपने कार्यक्रम के बारे में सूचित करते हैं, वैसे ही खिलाड़ियों को भी इस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की लोकप्रियता और पहचान के कारण उनका ध्यान हमेशा आकर्षित होता है और इस वजह से सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।

उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इंग्लैंड में फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ कई बार अनचाही घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटने और अप्रत्याशित स्थिति का सामना करते देखा है। उसी तरह की परिस्थितियों का अंदेशा क्रिकेट खिलाड़ियों को भी रहना चाहिए। मंत्री ने कहा कि जिस होटल में वे रुके थे, वहां अचानक कई युवा वहां आ गए और खिलाड़ियों के निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप हुआ। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि एक लड़की ने उनके सामने खिलाड़ियों को चूम लिया, जिससे उनकी पहचान और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

कैलाश विजयवर्गीय ने जोर देकर कहा कि खेलकूद में महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन, खेल संस्थान और स्थानीय अधिकारियों से भी अपील की कि वे खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध करें। उनका मानना है कि केवल नियम और आदेश पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि हर खिलाड़ी और उसकी टीम को भी सुरक्षा के उपायों का पालन करना चाहिए।

इस घटना के बाद देशभर के खेल अधिकारियों और खिलाड़ियों के लिए यह चेतावनी और मार्गदर्शन का काम करेगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि खेल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और उनकी सुरक्षा के लिए सभी स्तर पर सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी चाहे राष्ट्रीय हों या अंतरराष्ट्रीय, किसी भी देश या शहर में खेल आयोजन के दौरान स्थानीय प्रशासन से संपर्क और सुरक्षा उपायों की जानकारी लेना अनिवार्य होना चाहिए। विश्लेषकों का मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान न केवल महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि खेल जगत और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने का भी संकेत देता है। इसके साथ ही यह संदेश जाता है कि खेल में प्रतिभा के साथ-साथ सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी सभी की साझा जिम्मेदारी है। इस तरह, इंदौर की घटना ने एक बार फिर खेल समुदाय और प्रशासन को सतर्क किया है और देशभर में महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर एक व्यापक बहस को जन्म दिया है।

मुरादाबाद में सिलेंडर फटने से रेस्टोरेंट में भीषण आग, एक महिला की मौत; परिवार के 10 सदस्य झुलसे

(जीएनएस)। मुरादाबाद। रामपुर रोड स्थित होटल क्लार्क इन के सामने रविवार रात एक भयावह अग्निकांड ने पूरे इलाके में आतंक मचा दिया। परी रेस्टोरेंट के ऊपर बने मकान में आतिशबाजी की चिंगारी से गैस सिलेंडर में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में आग ने तबाही मचा दी। आग की चपेट में आकर रेस्टोरेंट मालिक प्रदीप श्रीवास्तव की मां मायादेवी की मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के दस सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए।

जानकारी के अनुसार, प्रदीप श्रीवास्तव अपनी बेटी परी के नाम से दो मंजिला रेस्टोरेंट चला रहे हैं और परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता है। उसी समय रेस्टोरेंट के बराबर में एक वेक्यूएट हाल में बरात की तैयारी चल रही थी, जिसमें आतिशबाजी हो रही थी। चिंगारी रेस्टोरेंट की ऊपरी मंजिल में जा गिरी और गैस सिलेंडर में आग लग गई।

कुछ ही समय में पांच सिलेंडर फट गए और धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहशत में आ गया। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। ग्यारह फायर टेंडर मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में फंसे लोगों को अग्निशमन कर्मियों ने तीसरी मंजिल से सुरक्षित बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। झुलसे लोगों में रेस्टोरेंट मालिक प्रदीप श्रीवास्तव, उनकी पत्नी शिवानी सक्सेना, बच्चे परी और वैभव, बहन साधना, बहनोई सचिन भटनागर, पिता जयप्रकाश, भांजे शौर्य, अभिनव और वंश शामिल हैं। कई की हालत नाजुक बनी हुई है।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन न होने और आतिशबाजी के कारण यह हादसा हुआ प्रतीत होता है।

स्थानीय लोग और प्रशासन आग जैसी आपदाओं से बचाव के लिए नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। घटना ने इलाके में भय और चिंता का माहौल बना दिया है, जबकि प्रशासन ने प्रभावित परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल गोझारिया में आयोजित शतचंडी महायज्ञ में शामिल हुए

- ‘विकसित गुजरात’ के निर्माण के लिए ‘विकास और विरासत’ में संतुलन अनिवार्य : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- “यदि धर्म के साथ विज्ञान हो, तो किसी भी मुकाम पर पहुंचा जा सकता है”

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात भर में विक्रम संवत 2082 के नववर्ष का उत्सव हर्षोल्लास से मनाने के बाद के दिनों में, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल मेहसाणा जिले के गोझारिया में श्री उमिया माताजी मंदिर ट्रस्ट और समस्त पाटीदार समाज की ओर से आयोजित शतचंडी महायज्ञ के पावन अवसर पर सहभागी हुए।

उन्होंने सभी को नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सदैव यह कहते हैं कि, ‘विकास करना है, लेकिन विरासत का संरक्षण करते हुए’ और उनका यह मंत्र ही विकसित भारत के निर्माण का सच्चा मार्ग है। मुख्यमंत्री ने यज्ञों के महत्व पर बल देते हुए कहा कि अगर धर्म के साथ विज्ञान होगा, तभी हम निर्धारित मुकाम या मंजिल तक पहुंच सकते हैं।

उन्होंने गोझारिया गांव की खासियत की सराहना करते हुए कहा कि इस गांव में अपने काम को निर्विघ्न संपन्न करने की क्षमता तो है ही, साथ ही दूसरों के काम को भी पूरा करने की ताकत है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राम मंदिर के निर्माण के बाद देश में व्याप्त नई ऊर्जा के संदर्भ में राष्ट्र निर्माण में गुजरात की भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य ‘विकसित गुजरात’ के जरिए ही संभव होगा।

मुख्यमंत्री ने विकसित गुजरात के लिए हर गांव को विकसित बनाने और अंतिम छोर के प्रत्येक व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के सरकार के सार्थक प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

राज्य के आर्थिक विकास की गति को और तेज करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जोनवार वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की हैं। इस शृंखला के अंतर्गत पहली कॉन्फ्रेंस हाल ही में उत्तर गुजरात में आयोजित की गई थी।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि इस कॉन्फ्रेंस के परिणामस्वरूप तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ और 1200 से अधिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

उन्होंने उमिया माता से प्रार्थना की कि नववर्ष में गोझारिया गांव नए संकल्प ले और वे सभी संकल्प परिपूर्ण हों।

इस अवसर पर मेहसाणा के सांसद श्री हरिभाई पटेल ने कहा कि हम देश के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। इससे नई पीढ़ी में धार्मिक संस्कारों का सिंचन होता है। उन्होंने विकास की व्याख्या का विस्तार करते हुए कहा कि इसमें केवल सड़क आदि ही नहीं, बल्कि धार्मिकता और संस्कार भी शामिल हैं।

राज्य सभा सांसद श्री मयंक नायक ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस युग में आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म की दिशा में मोड़ने के लिए शतचंडी महायज्ञ का आयोजन करने के लिए आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने एक सांसद के रूप में गांव के विकास के लिए सदैव उपलब्ध रहने और गोझारिया गांव विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए, इसके लिए संकल्पबद्ध होने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर उमिया माता के दर्शन किए और महायज्ञ के लिए उदार हाथों से दान देने वाले दानदाताओं को सम्मानित भी किया। शतचंडी महायज्ञ के इस धार्मिक और भव्य कार्यक्रम में मेहसाणा के विधायक श्री मुकेश पटेल, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेयरमैन श्री विनोदभाई पटेल, मेहसाणा के कलेक्टर श्री एस.के. प्रजापति, श्री उमिया माताजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पाटीदार समाज के अग्रणी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

मुंबई सेंट्रल पर हरित पहल को मिला नया आयाम,ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर मशीन स्थापित

(जीएनएस)। पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा मुंबई सेंट्रल स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के स्टाफ कैंटीन में एक ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर (OWC) मशीन स्थापित की गई है। यह पर्यावरण-संवेदनशील पहल भोजन और रसोई अपशिष्ट के जिम्मेदार प्रबंधन की दिशा में मंडल के प्रयासों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो रेलवे परिसर में स्वच्छ और हरित पर्यावरण को प्रोत्साहित करने की उसकी सतत प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करती है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह पर्यावरण-अनुकूल जैविक अपशिष्ट परिवर्तक मशीन, रेलवे परिसर में खाद्य अपशिष्ट को कम करने और एक हरित एवं अधिक पर्यावरण-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगी। यह जैविक अपशिष्ट परिवर्तक पूरी तरह से स्वचालित, कॉम्पैक्ट और स्टेनलेस स्टील से बना है, जिसे कैंटीन से निकलने वाले गीले और रसोई के कचरे को संसाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन-वेसल डिहाइड्रेशन तकनीक का उपयोग करते हुए, यह मशीन जैविक कचरे को मिट्टी के पूरक या कम्पोस्टेबल बायोमास में बदल देती है, जिसका उपयोग कार्यालय परिसर में बागवानी और भूनिर्माण के लिए किया जा सकता है।

यह उन्नत कनवर्टर बिना किसी अतिरिक्त पदार्थ (जैसे चूरा या बैक्टीरिया) के काम करता है। यह गंध नियंत्रण, प्रेशर सील प्रोसेसिंग और शून्य गैस उत्सर्जन जैसी सुविधाओं से लैस है, जिससे निकास या जल निकासी प्रणाली की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह मशीन विभिन्न प्रकार के कचरे, जैसे कि रसोई के कचरे, बेकरी के सामान, टिशू पेपर और बगीचे के कचरे को संभालने में सक्षम है, जिससे कुशल और स्वच्छ अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

इस अभिनव आंतरिक समाधान को लागू करके, पश्चिम रेलवे ने बाहरी कचरा संग्रहण सेवाओं पर अपनी निर्भरता सफलतापूर्वक समाप्त कर दी है और अपने कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी की है। यह पहल भारतीय रेल के पर्यावरणीय स्थिरता, आत्मनिर्भरता और संसाधन संरक्षण के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। पश्चिम रेलवे इस उपलब्धि के साथ स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है तथा रेलवे नेटवर्क में पर्यावरण के प्रति जागरूक परिचालन के लिए एक उदाहरण स्थापित करती है।

बिहार चुनाव 2025: चुनाव आयोग सख्त, साइलेंस पीरियड में प्रचार और एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव और राज्य के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि साइलेंस पीरियड (मौन अवधि) के दौरान किसी भी तरह का चुनावी प्रचार, जनमत सर्वेक्षण या एग्जिट पोल का प्रसारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस कदम का उद्देश्य मतदाताओं को शांतिपूर्ण वातावरण में सोच-समझकर मतदान का निर्णय लेने का अवसर देना बताया गया है।

चुनाव इस बार दो चरणों में होंगे, जिसमें पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर 2025 को निर्धारित किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि इस अवधि

में किसी भी माध्यम से राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों का प्रचार, टीवी या रेडियो चैनलों पर डिबेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट या सोशल मीडिया प्रचार प्रतिबंधित होगा। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1)(ख) के तहत उल्लंघन करने वालों के लिए दो वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान रखा है। आयोग ने सभी मीडिया हाउस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और केबल नेटवर्क को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि साइलेंस पीरियड के दौरान चुनावी सामग्री का प्रसारण पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साइलेंस पीरियड के दौरान एग्जिट पोल पर भी रोक रहेगी। आयोग ने बताया कि 6 नवंबर की सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करना या उनके परिणाम प्रकाशित करना कानूनी अपराध माना जाएगा। यह प्रतिबंध धारा 126क के तहत लागू किया गया है।

चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग का यह कड़ा रुख मतदाता की स्वतंत्र और सोच-समझकर मतदान करने की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे न केवल मतदान की निष्पक्षता बनी रहेगी, बल्कि राजनीतिक दलों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे। आयोग ने राज्य प्रशासन और मीडिया को सख्ती से इस नियम के पालन पर नजर रखने के लिए निर्देशित किया है, ताकि बिहार चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।

छत्तीसगढ़ और झारखंड में मतांतरण पर ग्रामीणों की सख्त कार्रवाई, संस्कृति और धर्म वापसी को मिला जोर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासी और ग्रामीण समाज ने मतांतरण के बढ़ते खतरे के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। बस्तर जिले के सिड़मुर गांव में सुंदरादेवी मंदिर के पास लगाए गए बोर्ड में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पास्टर और पादरी का प्रवेश सख्त मना है। यह कदम ग्रामीणों में पनप रहे जनाक्रोश और अपनी संस्कृति की रक्षा की भावना को दर्शाता है।

भतरा जनजातीय बहुल इस गांव में चार दिन पहले हुई सामाजिक बैठक में ग्रामीणों ने एकमत होकर निर्णय लिया कि ईसाई मिशनरियों और उनसे जुड़े लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। लगभग 270 परिवारों वाले इस गांव के लोगों ने कहा कि अब उनकी संस्कृति, परंपरा और देवगुड़ियों की रक्षा अब वे स्वयं करेंगे। बुजुर्ग पाकलुराम भारती के अनुसार, अगर यह मतांतरण का चलन यूं ही चलता रहा तो बस्तर की हजारों साल पुरानी संस्कृति धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। गांववासियों ने यह भी बताया कि अब तक केवल सात-आठ परिवार मतांतरित हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके व्यापक असर को देखते हुए उन्होंने पहले से ही सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। उन गांवों में जहां 60-70 परिवार तक मतांतरित हो चुके हैं, वहां सामाजिक विभाजन और तनाव आम हो चुका है। सिड़मुर में कुछ वर्षों पहले मतांतरित हुए बलराम कश्यप के परिवार का उदाहरण भी सामने आया। बलराम की मां कुष्ठ रोग से पीड़ित थीं और पादरी ने कहा था कि प्रार्थना से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हालांकि बीमारी नहीं गई, लेकिन पूरा परिवार मतांतरित हो गया। उनके घर के आंगन में बना पक्का चर्च विवाद का केंद्र बन गया। ग्राम सभा के निर्णय के बाद इस परिवार को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा, और उनकी दुकान पर तीन दिनों से कोई ग्राहक नहीं आया। इसके अलावा, गांव की सीमा में अब मतांतरित परिवारों के शवों को दफनाने पर भी रोक लगा दी गई है। बस्तर में घर वापसी की पहल भी गति पकड़ रही है। सिड़मुर से लगे अलनार गांव में शनिवार को 25 वर्ष पहले मतांतरित हुए एक परिवार के आठ सदस्यों ने सनातन धर्म में वापसी की। इस कार्यक्रम के माध्यम से गांवों में अपने धर्म और संस्कृति को बनाए रखने का संदेश दिया गया। राजाराम तोड़ेम, प्रांतीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, का कहना है कि जनजातीय समाज अब जाग चुका है। अब गांव स्वयं तय कर रहे हैं कि कौन उनके बीच आ सकता है और कौन नहीं। उनका कहना है कि यह आंदोलन किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के पक्ष में है।

महाराष्ट्र महिला डॉक्टर सुसाइड केसः देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'छोटी बहन को इंसाफ मिलने तक चुप नहीं बैठेंगे'

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुई महिला डॉक्टर सुसाइड केस ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक चर्चा को गर्मा दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर अपना संज्ञान लेते हुए कहा कि मृतक महिला डॉक्टर को वे अपनी छोटी बहन मानते हैं और जब तक उसे न्याय नहीं मिलता, वे चुप नहीं बैठेंगे। फडणवीस ने कहा, "गुरुवार को हमारी छोटी बहन ने आत्महत्या कर ली, यह बेहद दुखद घटना है। उसने अपने हाथों पर आत्महत्या का कारण लिखा था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। आरोपी को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा।"

सीएम ने इस मामले में राजनीति करने वालों पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ लोग बेवजह पार्टी के नेताओं का नाम जोड़कर अफ़वाह फैला रहे हैं। फडणवीस ने कहा, "बिना वजह हमारे रंजीत दादा और पार्टी के विधायक सचिन पाटिल का नाम जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र के लोग हमें जानते हैं। अगर किसी पर जरा भी शक होता तो मैं खुद यह कार्यक्रम रद्द कर देता। हम ऐसे मामलों में पार्टी नहीं, इंसानियत देखते हैं। यह हमारी बहन का मामला है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा।"

सुसाइड नोट में महिला डॉक्टर ने सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर पर गंभीर आरोप लगाए थे। डॉक्टर ने लिखा कि बदने ने उनके साथ चार बार बलात्कार किया और पुलिस मामलों में आरोपियों के लिए फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव डाला। मना करने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। प्रशांत बनकर के परिवार का दावा है कि डॉक्टर और प्रशांत के बीच प्रेम संबंध थे। मूलरूप से बीड जिले की रहने वाली महिला डॉक्टर फलटन उप-जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थीं। सुसाइड नोट में यह भी उल्लेख था कि अस्पताल में दो निजी सहायकों ने उनसे सांसद से मिलने की बात कराई, जिन्होंने परोक्ष रूप से धमकी दी। हालांकि सांसद का नाम सीधे नहीं लिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि डॉक्टर का इशारा भाजपा के पूर्व सांसद रणजीत नाईक निंबालकर की ओर था। इस खुलासे के बाद राज्य की सियासत में हलचल बढ़ गई और शिवसेना (यूबीटी) के नेता अंबादास दानवे ने पूर्व सांसद पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

इस मामले ने महिला सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक हस्तक्षेप के सवाल को भी उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि फडणवीस का सीधा हस्तक्षेप और न्याय की मांग ने पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बढ़ा दिया है। साथ ही यह मामला पूरे राज्य में महिला कर्मचारियों और डॉक्टरों के सुरक्षित कार्यस्थल की आवश्यकता को भी सामने लाता है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कठोरतम सजा दी जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

देशभर में 8 हजार स्कूलों में शून्य छात्र, फिर भी तैनात हैं 20 हजार से अधिक शिक्षक : शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े चिंताजनक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय के ताजा आंकड़ों ने देश के स्कूल शिक्षा ढांचे की गंभीर विसंगतियों को सामने लाकर नई बहस खड़ी कर दी है। 2024-25 शैक्षणिक सत्र के अनुसार, देशभर में करीब 7,993 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी छात्र दाखिला नहीं हुआ, लेकिन इन स्कूलों में कुल 20,817 शिक्षक तैनात हैं। इस स्थिति ने शिक्षण संसाधनों के असंतुलन और स्कूल प्रबंधन की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

सबसे अधिक शून्य दाखिले वाले स्कूल पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में हैं। पश्चिम बंगाल में 3,812 ऐसे स्कूल हैं, जिनमें 17,965 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि तेलंगाना में 2,245 स्कूलों में 1,016 शिक्षक तैनात हैं। मध्य प्रदेश में 223 स्कूल ऐसे पाए गए हैं, जहां कोई छात्र नहीं है लेकिन शिक्षक तैनात हैं। इसके विपरीत, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में ऐसे कोई स्कूल नहीं थे। दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, अंडमान-निकोबार, दमन-दीव और चंडीगढ़ में भी शून्य दाखिले वाला कोई स्कूल नहीं पाया गया।

उत्तर प्रदेश में 81 ऐसे स्कूल हैं, जिनकी मान्यता यूपी बोर्ड पिछले तीन वर्षों से शून्य पंजीकरण के कारण रद्द करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ

अधिकारी ने बताया कि राज्यों को शून्य दाखिले वाले स्कूलों के मुद्दे का समाधान करने और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए कुछ स्कूलों का विलय करने की सलाह दी गई है।

साथ ही देशभर में 33 लाख से अधिक छात्र एकल-शिक्षक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक एकल-शिक्षक विद्यालय हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में छात्रों का पंजीकरण सबसे ज्यादा है। एकल-शिक्षक विद्यालयों की संख्या 2022-23 में 1,18,190 थी, जो 2023-24 में घटकर 1,10,971 रह गई, यानी लगभग छह प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़ा राज्य और केंद्र दोनों के लिए शिक्षा क्षेत्र में संसाधनों के असंतुलन और स्कूलों के बेहतर प्रबंधन की चुनौती को उजागर करता है। शिक्षकों का शून्य छात्र वाले स्कूलों में तैनात होना न केवल मानव संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि यह नीति निर्माताओं के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रभावी वितरण पर गंभीर सवाल भी खड़ा करता है।

आंकड़ों के अनुसार, शून्य दाखिले वाले स्कूलों के अधिकांश कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का कम होना, स्कूलों का विलुप्त होना या माता-पिता की स्कूलों के प्रति उदासीनता हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन स्कूलों का विलय, बहु-विद्यालय प्रणाली और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

इस रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि देश के शिक्षा ढांचे में संसाधनों का असमान वितरण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसे सुधारने के लिए नीति निर्धारकों, राज्य प्रशासन और शिक्षा अधिकारियों को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। केवल शिक्षक तैनात करने भर से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि इसे छात्रों की संख्या, स्कूलों की कार्यप्रणाली और संसाधनों के उचित उपयोग के साथ संतुलित करना अनिवार्य है।

भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी घोषणा: मतदाता सूची के विशेष संशोधन (SIR) की प्रक्रिया शुरू, पहले चरण में 10-15 राज्य शामिल होंगे

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) की तारीखों की घोषणा करने की तैयारी पूरी कर ली है। आयोग आज शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह जानकारी साझा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची में सटीकता और चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ताकि आगामी चुनावों में मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित और निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

सूत्रों के अनुसार, SIR के पहले चरण में लगभग 10 से 15 राज्य शामिल होंगे। इनमें ऐसे राज्य भी शामिल हैं, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा। नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे, मृतक व्यक्तियों

के नाम हटाए जाएंगे, डुप्लिकेट प्रविष्टियों को समाप्त किया जाएगा और स्थानांतरण की जानकारी भी सही तरीके से दर्ज की जाएगी।

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग कर घर-घर सर्वेक्षण, दावे-आपत्तियों का निपटारा और मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र अपडेट करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा। वोटर हेल्पलाइन ऐप और ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के जरिए मतदाता जानकारी को डिजिटल रूप से सुरक्षित और सुलभ बनाया जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम का चुनावी परिदृश्य पर बड़ा असर पड़ेगा। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच मुकाबला कड़ा है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा की टक्कर चरम पर है, केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच प्रतिस्पर्धा जारी है, असम में भाजपा की स्थिति महत्वपूर्ण है और पुडुचेरी में कांग्रेस-डीएमके गठबंधन की भूमिका चुनावी रणनीतियों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। इन राज्यों में मतदाता सूची का अपडेट होना राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियों और रणनीतियों के लिए निर्णायक साबित होगा।

SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में त्रुटियों और गलतियों को ठीक करने के लिए दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। हर मतदाता को अपने नाम, पता और फोटो की पुष्टि करने का मौका मिलेगा। पहले चरण के सफल समापन के बाद अन्य राज्यों में भी चरणबद्ध तरीके से यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चुनाव आयोग की यह घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब राजनीतिक दल मतदाता आधार को मजबूत करने और पंजीकरण की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि SIR की प्रक्रिया से मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ेगी और आगामी चुनावों में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। यह कदम लोकतंत्र की मजबूती और जनता के मताधिकार की सुरक्षा की दिशा में एक अहम पहल है, जो चुनाव आयोग की चुनावी पारदर्शिता और जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है।

सड़क पर नशे और फर्जी लाइसेंस की जानलेवा साजिश: कुरनूल बस अग्निकांड की वह भयावह रात जब 20 लोग जिंदा जल गए

(जीएनएस)। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हुई बस अग्निकांड की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह कोई साधारण सड़क हादसा नहीं था, बल्कि लापरवाही, भ्रष्टाचार और नशे के मिले-जुले घातक परिणाम की एक भयावह मिसाल थी। 20 निर्दोष लोगों की जानें एक ही रात में चली गईं—कुछ सेकंडों की लापरवाही ने उन्हें ज़िंदा जला दिया।

घटना बीती शुक्रवार रात लगभग दो बजे की है। कुरनूल के चिन्ना टेकुरु गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक एक तेज़ रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बाइक पर दो युवक सवार थे—शिव शंकर और एरी स्वामी। दोनों नशे में धुत थे। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने कुछ ही देर पहले पास के ढाबे में खाना खाने के साथ शराब भी पी थी। टक्कर इतनी तेज़ थी कि शिव शंकर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वामी ने किसी तरह अपने दोस्त की लाश को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी दूर से आ रही एक बस ने उन्हें कुचल दिया। दुर्घटना यहीं खत्म नहीं हुई। बाइक बस के नीचे फंस गई और घसीटते-घसीटते बाइक का फ्यूल

टैंक फट गया। चिंगारियां उठीं और कुछ ही सेकंडों में बस आग के गोले में तब्दील हो गई। अंदर बैठे यात्रियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। चीखें, धुआं और जलती बस की भयावह लपटें—सबकुछ मानो किसी बुरे सपने की तरह था। उस बस का चालक मिरियाला लक्ष्मैया था। प्रारंभिक जांच में जो सच्चाई सामने आई, उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। लक्ष्मैया ने महज़ पांचवीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन उसने 10वीं पास का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया था। सरकारी नियमों के मुताबिक बस ड्राइवर को कम से कम आठवीं पास होना आवश्यक है। मतलब साफ है—उसके पास बस चलाने की कोई कानूनी योग्यता नहीं थी। फिर भी वह वर्षों से बड़े वाहनों को चला रहा था, क्योंकि सिस्टम ने उसकी सच्चाई कभी जांची ही नहीं।

कुरनूल रेंज के डीआईजी कोया प्रवीण ने बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बाइक सवार दोनों युवक नशे में थे। सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा कि वे पेट्रोल पंप से निकलते वक्त तेज़ रफ्तार में बाइक दौड़ा रहे थे। यह सब कुछ कुछ ही मिनटों में हुआ, लेकिन नतीजा इतना भयानक था कि 20 निर्दोष यात्री ज़िंदा जल गए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने इस घटना को "एक रोके जा सकने वाला नरसंहार" बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "नशे में वाहन चलाने वाले लोग आतंकवादी से कम नहीं हैं। कुरनूल की यह घटना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही का अपराध है।" उन्होंने चेतावनी दी कि अब से पुलिस नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ बिना किसी रहम के सख्त कार्रवाई करेगी।

यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि समाज के तीन गंभीर दोषों की कहानी है—एक भ्रष्ट व्यवस्था जिसने फर्जी सर्टिफिकेट से लाइसेंस बांटे, दूसरा नशे की वह मानसिकता जो लोगों को अपनी और दूसरों की जान से खिलवाड़ करने पर मजबूर करती है, और तीसरा आम नागरिकों की वह चुप्पी जो ऐसे खतरनाक व्यवहार को रोज़ाना सड़क पर देखने के बावजूद अनदेखा कर देती है। कुरनूल की उस रात की राख में सिर्फ एक बस नहीं जली, बल्कि वह पूरी चेतना जल गई जो हमें सावधानी और जिम्मेदारी सिखाती है। 20 परिवार उजड़ गए, कई बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया। पर सवाल यही है—क्या इस भयावह सबक के बाद भी हम कुछ सीखेंगे? या फिर अगली बार भी कोई नशे में धुत बाइक सवार और फर्जी लाइसेंसधारी ड्राइवर किसी और बस को आग के हवाले कर देगा?

तेजस्वी यादव का वक्फ अधिनियम पर हमला, कहा: 'इंडिया गठबंधन सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंका जाएगा'

(जीएनएस)। कटिहार। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रविवार को कटिहार में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वक्फ (संशोधन) अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। यादव ने अपने पिता और RJD प्रमुख लालू प्रसाद का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी देश में सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया और उनका उद्देश्य हमेशा समाज के पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के हित में रहा। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनकी सरकार हमेशा उन ताकतों का समर्थन करती रही है, जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठन राज्य और देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भाजपा को निशाने पर लेते हुए उन्होंने उसे 'भारत जलाओ पार्टी' कहा। उन्होंने दोहराया कि सत्ता में आने पर वक्फ एक्ट को हटाया

जाएगा और इस मुद्दे पर उनकी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, जिसे अप्रैल 2025 में संसद में पास किया गया, NDA का कहना है कि यह कानून पिछड़े मुसलमानों और समुदाय की महिलाओं के लिए पारदर्शिता और सशक्तिकरण का जरिया है। लेकिन विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन मानता है। RJD MLC मोहम्मद कारी सोहैब ने भी इस मामले में बयान दिया कि यदि यादव मुख्यमंत्री बने तो "वक्फ बिल सहित सभी बिल फाड़ दिए जाएंगे", जिससे राजनीतिक विवाद और गरम हो गया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए केंद्रीय कानून को हटाना या बदलना संभव नहीं है।

तेजस्वी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार की 20 साल पुरानी सरकार से थक चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उन्होंने यह भी वादा किया कि सत्ता में आने पर सीमांचल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सीमांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने NDA पर चुनावी वादों की नकल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का वादा उनकी पार्टी ने किया था, जिसे सरकार ने अपने तरीके से लागू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उनका वादा 2,000 प्रति माह तक पेंशन बढ़ाने का था, जबकि वर्तमान सरकार ने इसे घटाकर लागू किया। इस बयान के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों ने इसे चुनावी रणनीति और जनता को भ्रमित करने वाला कदम बताया। तेजस्वी का यह बयान अगले कुछ दिनों तक सियासी बहस का विषय बना रहेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा एक महत्वपूर्ण बहस का केंद्र बन सकता है।